इलाहाबाद जिले में एक नये डाकघर का खोला जाना

1482. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के मोहल्ला कृष्णा नगर (कादीगंज) में एक नया डाकघर खोले जाने की जनता की मांग पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) नये डाकघर के कब तक खोल दिए जाने की सम्भावना है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसमें क्या अड़चनें हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी०रंगैयानायडू) : (क) सरकार ने मोहल्ला कृष्ण नगर (कैदगंज) में जमुना बैंक रोड में एक नया डाकघर खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया था लेकिन यह पाया कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार यह प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं है ।

(ख) चूंकि यह प्रस्ताव निर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है, अत: इस डाकघर को खोले जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए एक मानदंड यह भी है कि 20 लाख और इससे कम जनसंख्या वाले शहरों में मौजुदा डाकघर में प्रस्तावित डाकघर की न्यूनतम दूरी 2 कि. मी. होनी चाहिए। मोहल्ला कृष्णा नगर में प्रस्तावित डाकघर के मामले में नजदीकी डाकघर कृष्ण नगर 1.2 कि. मी. की दूरी पर है। अत: डाकघर खोलने के मामले में दूरी का मानदंड पूरा न होना मुख्य बाधा है।

Increase in private vehicles in Delhi

1483. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been phenomenal growth in the number of private vehicles in Delhi during the last few years;

(b) whether it is also a fact that there has not been any significant increase in the number of public transport vehicles vis-a-vis requirements in Delhi;

(c) whether the increase in private vehicles is attributable to inadequate public transport services;

(d) whether it is a fact that adequate public transport facilities can help in checking petrol consumption and air pollution; and

(e) if so, what steps are being taken in the above matters?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir, to some extent.

(d) Yes, Sir.

(e) With a view to wean away passengers who presently use personalised vehicles to public transport, a scheme of 'Special State Carriage Permits' to be given to private operators at a fare structure higher than that of DTC, with more comforts has been recommended to Delhi Administration by the Government.

Delhi Administration had engaged M/s. RITES to take up a techno-economic feasibility study for the introduction of Mass Rapid Transport System for Delhi. The report was submitted to Delhi Administration. The Government of India in consultation with the Delhi Administration have constituted a Steering Committee to take preparatory action.

Delhi Administration have also been advised to grant additional stage carriage permits to private operators.